तापमान

भोपाल	18.3°	8.4°
इंदौर	24.2°	12.5°
जबलपुर	20.8°	9.0°
ग्वालियर	20.3°	9.9°

दैनिक
नईदुनिया

भोपाल एवं सागर से एकसाथ प्रकाशित

वर्ष- 78
(भोपाल : वर्ष 40 अंक 35,पृष्ठ 12)
गुरुवार 2 जनवरी 2025
राजधानी संस्करण
कीमतः 3:00 रुपये

राजधानी... पुलिस की यक्रियताः शांति व .....

खेल... वेस्ट हैम यूनाइटेड के स्ट्राइकर माइकल ...

व्यापार... एअर इंडिया आने वाले वर्षों में अपनी वैश्विक...

देश-विदेश... पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने नए साल के ...

www.naiduniaonline.com

केन्द्रीय मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण फैसले .....

नए साल पर केंद्र ने दिया किसानों को तोहफा, खाद पर सब्सिडी बढ़ीः वैष्णव

नई दिल्ली (एजेंसी)।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नव वर्ष में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की पहली बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों का उल्लेख करते हुए बुधवार को दोहराया कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

श्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हमें अपने सभी किसान बहनों और भाइयों पर गर्व है जो हमारे देश को भोजन उपलब्ध कराने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। 2025 की पहली कैबिनेट बैठक हमारे किसानों की समृद्धि बढ़ाने के लिए समर्पित है। मुझे खुशी है कि इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं। उल्लेखनीय है कि मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्र सरकार ने 50 किलोग्राम की डीएपी उर्वरक की बोरी का मूल्य 1350 रुपए निर्धारित करने के साथ साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों की आवश्यकता के अनुसार संशोधन करने का फैसला किया है। केंद्र सरकार द्वारा यह सब्सिडी (स्पेशल पैकेज) 31 दिसंबर 2025 तक दी गई है। केंद्र सरकार ने 50 किलोग्राम की डीएपी उर्वरक प्रति बोरी का मूल्य 1350 रुपए निर्धारित करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों की आवश्यकता के अनुसार संशोधन करने का फैसला किया है।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद मीडिया को बताया कि किसानों को डीएपी का 50 किलो का बैग 1,350 रुपये में उपलब्ध कराया जाएगा। यह %वन टाइम पैकेज काफी महत्वपूर्ण है। पड़ोस के देशों में डीएपी का 50 किलो का बैग तीन हजार रुपये से ज्यादा में मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भले ही कैसे भी स्थिति आ जाए हमें अपने किसानों को सुरक्षित करना है। उनके ऊपर बोझ नहीं डालना है। उन्होंने राज्य सरकारों से अपील की है कि डीएपी के नाम पर कुछ लोग किसानों को ठगने का प्रयास करेंगे। मैं उन्हें चेतावनी देता हूं कि अगर कोई ऐसा करते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने बताया कि इस पैकेज पर लगभग 3,850 करोड़ रुपये की लागत होगी। साल 2014 से लेकर अब तक कोविड-19 का वह दौर भी आया जब स्थिति काफी खराब थी। लेकिन, हमारी सरकार और पीएम मोदी ने सुनिश्चित किया है कि किसानों को बाजार के उतार-चढ़ाव का खामियाजा न उठाना पड़े। 2014-24 तक उर्वरक सब्सिडी 11.9 लाख करोड़ रुपये थी जो 2004-14 के दौरान दी गई सब्सिडी से दोगुनी से भी अधिक है। कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने को मंजूरी दी। इस निर्णय से 2025-26 तक देश भर के किसानों के लिए न रोकी जा सकने वाली प्राकृतिक आपदाओं से फसलों के जोखिम कवरेज में मदद मिलेगी। इसके अलावा, योजना के क्रियान्वयन में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी के उपयोग से पारदर्शिता और दावा गणना और निपटान में वृद्धि होगी। इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 824.77 करोड़ रुपये की राशि के साथ नवाचार और प्रौद्योगिकी कोष (एफआईएटी) के निर्माण को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को यहां हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में फसल बीमा योजना के मौजूदा क्षेत्र का विस्तार करने और डीएपी की बोरी मूल्य 1350 रुपए निर्धारित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि किसानों को सस्ती कीमतों पर डीएपी पर सब्सिडी जारी रखने के लिए एकमुश्त विशेष पैकेज के विस्तार को मंजूरी दी गयी है। यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव और आपूर्ति में बाधा के बावजूद किसानों को डीएपी की 50 किलोग्राम की बोरी 1350 रुपए में ही मिलेगी। इसकी अतिरिक्त कीमत सरकार वहन करेगी। सरकार ने किसानों को सब्सिडी वाले, सस्ती और उचित कीमतों पर डीएपी की उपलब्धता सुनिश्चित की है।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक 69,515.71 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ वर्ष 2025-26 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को जारी रखने को मंजूरी दी है। इस निर्णय से वर्ष 2025-26 तक देश भर के किसानों के लिए प्राकृतिक आपदाओं से फसलों के जोखिम से निपटने में मदद मिलेगी।

रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित कियाः राजनाथ

नई दिल्ली (एजेंसी)।

रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को 'सुधारों का वर्ष' घोषित किया है, जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों को एक साथ कई क्षेत्रों में संचालन में सक्षम बनाना और उन्नत प्रौद्योगिकी से लैस लड़ाकू सेना बनाना है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं, सुधारों और प्रगति की समीक्षा के लिए मंत्रालय के सभी सचिवों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में कहा कि श्री सिंह ने विश्वास जताया कि यह सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। उन्होंने कहा, यह देश की रक्षा तैयारियों में अभूतपूर्व प्रगति की नींव रखेगा, इस प्रकार 21वीं सदी की चुनौतियों के बीच राष्ट्र की सुरक्षा और संप्रभुता सुनिश्चित करने की तैयारी करेगा। सुधारों का उद्देश्य संयुक्तता और एकीकरण पहल को और मजबूत करना और एकीकृत थिएटर कमान की स्थापना को सुविधाजनक बनाना होगा। रक्षा मंत्रालय ने 2025 में साइबर और अंतरिक्ष जैसे नए डोमेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, हाइपरसोनिक्स और रोबोटिक्स जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों सहित केंद्रित हस्तक्षेप के लिए व्यापक क्षेत्रों की पहचान की है। इसके अलावा, भविष्य के युद्धों को जीतने के लिए आवश्यक संबंधित रणनीति, तकनीक और प्रक्रियाएं भी विकसित की जाएंगी।

एक अन्य क्षेत्र जिसकी पहचान की गई है, वह है अधिग्रहण प्रक्रियाएं, जिन्हें तेज और मजबूत क्षमता विकास की सुविधा के लिए सरल और समय-संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है। रक्षा क्षेत्र और नागरिक उद्योगों के बीच प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और ज्ञान साझा करने को सुविधाजनक बनाने, व्यापार करने में आसानी में सुधार करके सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सरकार रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग, अक्षमताओं को खत्म करने और संसाधनों को अनुकूलित करने के लिए प्रभावी नागरिक-सैन्य समन्वय पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। एक अन्य फोकस क्षेत्र भारत को रक्षा उत्पादों के एक विश्वसनीय निर्यातक के रूप में स्थापित करना, ज्ञान साझा करने और संसाधन एकीकरण के लिए भारतीय उद्योगों और विदेशी मूल उपकरण निर्माताओं के बीच अनुसंधान और विकास और साझेदारी को बढ़ावा देना भी होगा। इस वर्ष के दौरान पूर्व सैनिकों के कल्याण पर भी ध्यान केंद्रित किया जायेगा और उनकी विशेषज्ञता का लाभ उठाया जाएगा। सरकार उनके लिए कल्याण उपायों के अनुकूलन की दिशा में भी काम करेगी।

मोदी 6 को जम्मू रेल डिवीजन की रखेंगे आधारशिला

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जनवरी को वर्चुअली जम्मू रेल डिवीजन की आधारशिला रखेंगे। इससे जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के पठानकोट क्षेत्रों की फिरोजपुर डिवीजन पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। वर्तमान में जम्मू उत्तर रेलवे के फिरोजपुर रेलवे डिवीजन के अंतर्गत आता है।जम्मू उत्तर रेलवे के अंतर्गत छठा मंडल (डिवीजन) होगा। उत्तर रेलवे बुनियादी ढांचे के लिए एक अलग डिवीजन की मांग लंबे समय से लंबित थी।

खास-खबरें

एयर मार्शल मिश्रा ने वायु सेना की पश्चिमी कमान की बागडोर संभाली

नई दिल्ली (एजेंसी)। एयर मार्शल जितेन्द्र मिश्रा ने बुधवार को भारतीय वायु सेना की पश्चिमी कमान की बागडोर संभाल ली। एयर मार्शल मिश्रा को 6 दिसंबर 1986 को लड़ाकू पायलट के रूप में भारतीय वायु सेना में कमीशन दिया गया था। वह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पुणे, एयर फोर्स टेस्ट पायलट स्कूल, बैंगलोर, एयर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज, यूएसए और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज, यूके के पूर्व छात्र हैं। एक फाइटर कॉम्बैट लीडर और एक प्रायोगिक टेस्ट पायलट के तौर पर एयर मार्शल मिश्रा के पास 3000 घंटे से अधिक उड़ान का अनुभव है।

भाजपा के विरोध के बावजूद पुजारी-ग्रंथी सम्मान योजना लागू होगीः आप

नई दिल्ली (एजेंसी)। आम आदमी पार्टी (आप) ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) चाहे जितना विरोध कर ले, लेकिन दिल्ली में 'आप' की सरकार बनने के बाद श्री अरविंद केजरीवाल पुजारी-ग्रंथी सम्मान योजना को लागू करके रहेंगे।

आप के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बुधवार को कहा कि जब से पुजारियों और ग्रंथियों के लिए 18,000 रुपए प्रति माह की सम्मान राशि देने की घोषणा की है, तब से पूरी भाजपा अरविंद केजरीवाल को गाली देने में जुट गई है।

प्रदेश में कड़ाके की ठंड और कोहरे की मार

भोपाल (काप्र)।

नए साल की शुरुआत के साथ ही मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का प्रभाव भी बढ़ने लगा है। प्रदेश के कई जिलों में तापमान में भारी गिरावट आई है, जिसके चलते शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है।

वहीं राजधानी भोपाल कोहरे की आगोश में नजर आया। सीजन का सबसे घना कोहरा देखने को मिला। विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम नजर आई। मावठे की बारिश के बाद

कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट

घने कोहरे का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। देव दर्शन के साथ लोगों ने की नववर्ष की शुरुआत, नए साल पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन का जनता दरबार पर मंथन, आज से मोदी की चार जातियों पर विशेष फोकसभोपाल, ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी, दतिया, नीमच, मंदसौर, आगर-मालवा, राजगढ़, सीहोर, रायसेन, विदिशा, सागर, निवाड़ी समेत 32 जिलों में कोहरे का प्रभाव देखने को मिल रहा (शेष पेज 2 पर)

देश में भूगर्भ जल रिचार्ज में 7 साल के दौरान अच्छी प्रगति

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश में कुल वार्षिक भूगर्भ जल रिचार्ज में पिछले 7 वर्ष के दौरान 5 गुना वृद्धि हुई है। आकलन, 2024 के अनुसार वर्ष 2017 में देश में भूगर्भ जल रिचार्ज वार्षिक 3 अब घन मीटर हुआ करता था जो अब बढ़कर 15 बीसीएम तक पहुंच गया है।परिवर्तनशील भूगर्भ जल रिचार्ज की स्थिति का मूल्यांकन केंद्रीय भूगर्भ जल बोर्ड द्वारा राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्र के साथ संयुक्त रूप से किया गया है। इसका उद्देश्य है कि इस रिपोर्ट के आधार पर संबद्ध पक्ष आवश्यकता पड़ने पर उपयुक्त हस्तक्षेप कर सकें।

झूठे वादे करने में माहिर अरविंद केजरीवाल

जो कहते हैं उससे मुकर जाते हैं : सुधांशु

नई दिल्ली (एजेंसी)।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आम आदमी पार्टी पर आज आरोप लगाया कि देश की राजनीति में बदलाव का सपना दिखा कर सत्ता में आयी इस पार्टी पर बीते साल भ्रष्टाचार एवं अपराध के जितने विविधतापूर्ण आरोप लगे हैं वैसे आरोप किसी अन्य पार्टी पर नहीं लगे।

भाजपा के प्रवक्ता एवं सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने पार्टी के केन्द्रीय कार्यालय पर आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वर्ष 2024 का वर्ष गुजर चुका है और ये भारत की राजनीति और विश्व में एक अद्भुत, विस्मयकारी, सुखद और विचित्र अनेक प्रकार की स्मृतियां छोड़ गया है। उन्होंने कहा कि 2024 में जहां एक तरफ 500 वर्षों के बाद प्रभु श्रीराम मंदिर का उद्घाटन हुआ। 60 वर्ष के बाद देश में लगातार तीसरी बार किसी प्रधानमंत्री को सरकार बनाने का मौका मिला। संविधान के 75 वर्ष पूर्ण (शेष पेज 2 पर)

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के स्मारक को लेकर प्रक्रिया शुरू

नई दिल्ली (एजेंसी)।

केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का स्मारक बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। संभावित स्थलों के सुझाव उनके परिवार के साथ साझा किए गए हैं, जिनसे निर्माण कार्य शुरू करने के लिए एक स्थान का चयन करने के लिए कहा गया है।

स्मारक के लिए राजघाट, राष्ट्रीय स्मृति स्थल या किसान घाट के पास लगभग 1 से 1.5 एकड़ जमीन प्रस्तावित की गई है। शहरी विकास मंत्रालय के अधिकारी पहले ही इन क्षेत्रों का निरीक्षण कर चुके हैं। वहीं, मनमोहन सिंह के परिवार को कुछ विकल्प दिए गए हैं। नई नीति के तहत स्मारक के लिए जमीन केवल किसी ट्रस्ट को ही आवंटित की जा सकेगी।

मंदिर तोड़ने वाले फैसले को एलजी ने दी मंजूरीः आतिशी

नई दिल्ली (एजेंसी)।

दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने बुधवार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर नया हमला बोलते हुए अपना आरोप दोहराया कि उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में मंदिरों और अन्य धार्मिक संरचनाओं को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। आप नेता ने अपने आरोपों के समर्थन में दस्तावेजी सबूत होने का दावा किया। आतिशी की टिप्पणी तब आई जब उपराज्यपाल ने मंगलवार को उनके पहले के आरोपों को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि मुख्यमंत्री गंदी राजनीति खेल रहे थे।

आतिशी ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में मंदिरों और बौद्ध मंदिरों को ध्वस्त करने की योजना बना रही है। एक (शेष पेज 2 पर)

जैश के आतंकियों को मदद देने वालों पर कसा शिकंजा, 4 गिरफ्तार

जम्मू (एजेंसी)। जम्मू कश्मीर के सांबा और जम्मू जिलों में दो कथित अपराधियों को जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) और स्वापक औषधि एवं मन प्रभावी पदार्थ (पीआईटी-एनडीपीएस) अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि विजयपुर निवासी राहुल कुमार को हिरासत में लेने का औपचारिक आदेश सांबा जिला मजिस्ट्रेट से प्राप्त करने के बाद पीएसए के तहत मामला दर्ज किया गया और बाद में उसे कठुआ जिला जेल ले जाया गया। उन्होंने कहा कि कुमार की कुख्यात आपराधिक गतिविधियों ने क्षेत्र में सार्वजनिक शांति और सौहार्द के लिए गंभीर खतरा पैदा किया है। सुरक्षा बलों ने कहा कि उन्होंने जम्मू-कश्मीर के त्राल से प्रतिबंधित संगठन जैश-ए-मोहम्मद के चार आतंकवादी सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। सुरक्षा बलों ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी के दौरान उनके पास से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई। जम्मू कश्मीर के सांबा और जम्मू जिलों में दो कथित अपराधियों को जन सुरक्षा अधिनियम और स्वापक औषधि एवं मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि विजयपुर निवासी राहुल कुमार को हिरासत में लेने का औपचारिक आदेश सांबा जिला मजिस्ट्रेट से प्राप्त करने के बाद पीएसए के तहत मामला दर्ज किया (शेष पेज 2 पर)

जय बापू, जय भीम, जय संविधान अभियान शुरू करेगी कांग्रेस

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस 3 जनवरी को सभी ब्लॉकों, जिलों और राज्यों में अपना जय बापू, जय भीम, जय संविधान अभियान शुरू करेगी। यह अभियान 26 जनवरी को महू में एक सार्वजनिक रैली में समाप्त होगा। यह अभियान 27 दिसंबर को शुरू किया जाना था। लेकिन 26 दिसंबर को पूर्व प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह के निधन और उनके सम्मान में सात दिवसीय शोक की घोषणा के मद्देनजर निलंबित कर दिया गया था। अभियान आयोजित करने का निर्णय 26 दिसंबर को बेलगावी में कांग्रेस कार्य समिति की आखिरी बैठक में लिया गया था। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि 26 दिसंबर के सीडब्ल्यूसी प्रस्ताव के कार्यान्वयन को सिंह के प्रति गहरे सम्मान और श्रद्धा के प्रतीक के रूप में एक सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया गया था।

स्पेशल खबर *छह से 10 जनवरी तक स्कूलों-कॉलेजों में ...*

चलाएं सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम : योगी

लखनऊ (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 5 जनवरी तक हर हाल में बैठक संपन्न कर लें।

छह से 10 जनवरी तक सभी स्कूलों-कॉलेजों में सड़क सुरक्षा नियमों से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। सीएम योगी ने यह भी निर्देश दिए कि महाकुंभ में बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए पीआरडी और होमगार्डों की संख्या बढ़ाई जाए। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में हर वर्ष हो रही 23-25 हजार मौतें देश और राज्य की क्षति है। यह दुर्घटनाएं जागरूकता के अभाव में होती हैं। सड़क सुरक्षा माह सिर्फ लखनऊ तक सीमित न रहे, बल्कि इसे प्रदेश के सभी 75 जनपदों में सुचारू रूप से संपन्न कराया जाए। इसके अतिरिक्त भी हर माह जनपदों में

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा की बैठक हो, जिसमें पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त, आरटीओ, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी आदि उपस्थित रहें। जनपद स्तर पर हुए कार्यों की प्रोग्रेस को लेकर हर तीसरे महीने शासन स्तर पर मूल्यांकन किया जाए। सीएम योगी ने आगे कहा कि उन जनपदों और स्थलों को चिह्नित करें, जहां अधिक दुर्घटनाएं संभावित हैं। इसके लिए कारणों का पता करते हुए समाधान की कार्ययोजना बनाई जाए। नाबालिग ई-रिक्शा और अन्य वाहनों का संचालन न कर पाएं, इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ई-रिक्शा के रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई सुचारू रूप से की जाए। सड़कों पर अनिवार्य रूप से साइनेज लगाए (शेष पेज 2 पर)